एस. जे. कोक इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड वगैरह

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड वगैरह

(सिविल अपील सं. 3399-3400 2015)

अप्रैल 08, 2015

[न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे]

भारत का संविधान, 1950––अनुच्छेद 141, 14–– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल कंपनी (सीसीएल) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (ई-नीलामी) द्वारा कोयले की बिक्री की योजना– उक्त योजना को अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड के मामले में अधिकारातीत घोषित कर दिया गया– सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले में कोयला उपभोक्ताओं से कोयला कंपनियों द्वारा वसूल की गई अतिरिक्त राशि को 6% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश जारी किया गया, जो योजना को कानून में खराब घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें देय हो गई थी– इसके बाद, तत्काल कोयला उपभोक्ता ने 6% ब्याज के साथ ली गई अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष कोयला कंपनी के खिलाफ रिट याचिका दायर की— एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली– हालाँकि, खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया– अपील पर, माना गया: एक बार जब इस न्यायालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में एक तर्कसंगत आदेश पारित करके मुद्दे का फैसला किया, तो उक्त निर्णय में घोषित अनुपात निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर समान प्रकृति के लिस का निर्णय लेते समय इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी था– नीचे की दोनों अदालतें उक्त निर्णय पर ध्यान देने के लिए कानूनी बाध्यता के अधीन थीं और फिर उसमें निर्धारित कानून के अनुरूप रिट

याचिका/अपील पर निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि दोनों मामलों में शामिल विवाद प्रकृति में समान था— इस मुद्दे को तय करने में नीचे की दोनों अदालतों के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दी जा सकती, हालांकि यह उलटफेर का था— – तथ्यों के आधार पर, पिछले मुकदमों में इस न्यायालय द्वारा नागरिकों के पक्ष में निर्धारित किए गए वैध दावे जिनकी जानकारी सीसीएल को थी, को विफल करने के लिए सीसीएल द्वारा अस्थिर दलीलें उठाई जा रही थीं– इस प्रकार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले के कोयला उपभोक्ताओं के साथ समानता के आधार पर तत्काल कोयला उपभोक्ता को अतिरिक्त राशि की वापसी के लाभ से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है— सीसीएल को प्रत्येक कोयला उपभोक्ता के दावे का सत्यापन करने और 6% ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश जारी किया गया।

रिट याचिकाकर्ताओं-कोयला उपभोक्ताओं की अपीलों को स्वीकार करते हुए और कोयला कंपनी-सीसीएल की अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसलिए, एक बार जब इस न्यायालय ने 10.08.20122 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में एक तर्कसंगत आदेश पारित करके मुद्दे का फैसला किया, तो उक्त निर्णय में घोषित अनुपात निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर समान प्रकृति के लिस का निर्णय लेते समय इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी था। इसलिए, नीचे की दोनों न्यायालय उक्त निर्णय पर ध्यान देने के लिए कानूनी बाध्यता के अधीन थीं और फिर उसमें निर्धारित कानून के अनुरूप रिट याचिका/अपील पर निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि दोनों मामलों में शामिल विवाद प्रकृति में समान था। इस मुद्दे को तय करने में नीचे की दोनों अदालतों के दृष्टिकोण को हालांकि यह उलटफेर का था, समर्थन नहीं दिया जा सकता। दोनों

अदालतें ऐसा करने में विफल रहीं, जिससे विवादित निर्णय कानून की नजर में खराब हो गया। [पैरा 35,36] [833-सी-ई]

1.2 इस न्यायालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स मामले में निश्चित रूप से स्पष्टता से कहा कि अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया में दिए गए निर्णय का लाभ उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो उन मामलों में पक्षकार थे, बल्कि यह इस तथ्य की परवाह किए बिना सभी के लिए होगा कि वे पक्षकार थे या नहीं। इसलिए, इस न्यायालय ने अतिरिक्त राशि की वापसी की राहत को बरकरार रखा, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ता को दी गई थी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले के रिट याचिकाकर्ताओं के साथ समानता के आधार पर तत्काल कंपनियों को लाभ देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, अनुचित संवर्धन के मुद्दे पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अनुरोध पर इस न्यायालय के समक्ष रखी गई स्पष्ट चुनौती को खारिज कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, इसकी सराहना नहीं की जा सकती कि किस आधार पर, ईस्टर्न कोल कंपनी जैसी एक अन्य कोयला कंपनी को अब इन कार्यवाहियों में फिर से वही याचिका उठाने की अनुमति दी जा सकती है, केवल इसलिए कि यह मामला किसी अन्य उच्च न्यायालय से उत्पन्न हुआ है। इस न्यायालय ने इसी तरह के विवाद से निपटने के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स के मामले में अनुचित संवर्धन के मुद्दे को खारिज कर दिया था, यही मुद्दा अब किसी अन्य कोयला कंपनी के लिए समान लंबित कार्यवाही में उठाने के लिए उपलब्ध नहीं है। यह तब और भी अधिक है जब दोनों मामलों में कोई विशिष्ट विशेषता सामने नहीं लाई गई। खंड पीठ ने जब देरी और कमियों के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज करने की कार्यवाही की तो उसने जो दृष्टिकोण अपनाया, उससे सहमति नहीं जताई जा सकती। एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर रिट याचिकाओं पर सही ढंग से विचार किया और रिट याचिका में कंपनियों द्वारा किए गए दावे के अनुसार राहत

प्रदान की और खंड पीठ को एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखना चाहिए था। [पैरा 37-39, 41, 43] [835-जी-एच; 836-ए-बी; 837-बी-डी; 838-जी]

1.3 सीसीएल द्वारा अपनाए गए रुख और जिस तरह से उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में सभी चरणों में इस न्यायालय द्वारा उनके फैसले के बावजूद समान दलीलें देकर मामले लड़े, उसे ध्यान में रखते हुए हमें इससे यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि पिछले मुकदमों में इस न्यायालय द्वारा नागरिकों के पक्ष में निर्धारित किए गए वैध दावे जिनकी जानकारी सीसीएल को थी, को विफल करने के लिए सीसीएल द्वारा अरक्षणीय दलीलें उठाई जा रही थीं। सीसीएल को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक रिट याचिकाकर्ताओं के दावे को सत्यापित करे और फिर किसी भी राशि का समायोजन करने के बाद, यदि रिट याचिकाकर्ताओं को उनके दावे के खिलाफ पहले ही भुगतान किया गया पाया जाता है, तो शेष राशि 6% ब्याज के साथ संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं को वापस कर दे। [पैरा 47,50] [840-बी, एफ]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम टेटुलिया कोक प्लांट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2011 (9) एससीआर 1103: (2011) 14 एससीसी 624––पर भरोसा किया गया।

अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2005 (5) पूरक एससीआर 718: (2006) 9 एससीसी 228; अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006 (9) पूरक एससीआर 954: (2007) 2 एससीसी 640; भगवती कोक इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड एवं अन्य बनाम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य सीडब्ल्यूजेसी 7753/2008; फर्म कालूराम सीताराम बनाम द डोमिनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1954 बॉम्बे 50 - संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

2005 (5) पूरक एससीआर 718	संदर्भित किया गया	पैरा 9
2006 (9) पूरक एससीआर 954	संदर्भित किया गया	पैरा 10
2011 (9) एससीआर 1103	भरोसा किया गया	पैरा 44
एआईआर 1954 बॉम्बे 50	संदर्भित किया गया	पैरा 46

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 से सिविल अपील सं 3399-3400

2012 की एलपीए संख्या 1574 और 1581 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2012 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

2015 की सिविल अपील संख्या 3419, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410 और 3411

एस. डी. संजय, देवाशीष भरूका, अनु त्यागी, गौरव अग्रवाल, अनीप सचथे, शगुन मट्टा उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा दिया गया था

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें एल.पी.ए. संख्या 1574, 1581, 1504, 1571, 1597 एवं 1591 2012 में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2012 के विरुद्ध दायर की गई हैं तथा 2013 की एल.पी.ए. संख्या 85 में दिनांक 18.01.2013 के निर्णय/आदेश जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (बाद में "सीसीएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को रद्द करते हुए एसजे कोक इंडस्ट्रीज प्रा.

लिमिटेड वगैरह वगैरह (इसके बाद "कंपनियों" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3. इन अपीलों में शामिल मुद्दों को समझने के लिए, उन तथ्यों की पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है, जिनके कारण कंपनियों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्होंने इन अपीलों को जन्म दिया है।

4. ये कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। वे विभिन्न श्रेणियों के कोयले की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगे हुए हैं। सीसीएल भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो विभिन्न श्रेणियों के कोयले के उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। सीसीएल वर्तमान कंपनियों सहित कई थोक कोयला उपभोक्ताओं को कोयला बेचता है, जो कोयले से जुड़े उपभोक्ता हैं। कोयला एक आवश्यक वस्तु है, इसकी कीमतें और निपटान का तरीका समय-समय पर केंद्र सरकार/कोयला कंपनियों द्वारा बनाए गए अधिनियमों/विनियमों/नियंत्रण आदेशों और नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

5. पूरे देश में अपने उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री और वितरण को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, भारत संघ ने इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (ई-नीलामी) द्वारा कोयले की बिक्री के लिए वर्ष 2004-2005 में एक योजना लागू की। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ कोयले के विभिन्न ग्रेडों की बिक्री, वितरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित तरीके और प्रणाली प्रदान करती है। कोल इंडिया लिमिटेड और सीसीएल सहित इसकी कई सहायक कंपनियों ने इसके कार्यान्वयन के लिए योजना को अपनाया।

6. व्यापारियों और कोयले से जुड़ी कई कंपनियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके योजना की वैधता और मान्यता को चुनौती दी गई थी।

जहां तक वर्तमान कंपनियों का सवाल है, उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अंतरिम आदेश पारित कर रिट याचिकाकर्ताओं को योजना में निर्धारित कोयले की अधिसूचित कीमत और ई-नीलामी भारित औसत कीमत के बीच अंतर की राशि के लिए क्षतिपूर्ति बांड/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

7. कुछ उच्च न्यायालयों ने अंततः रिट याचिकाओं का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया और रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए योजना को अधिकारातीत घोषित कर दिया, जबकि कुछ उच्च न्यायालयों ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और योजना को कानूनी और उचित बताया। कुछ उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ लंबित रहीं। दोनों पक्षों द्वारा निपटाए गए मामलों से उत्पन्न अपील इस न्यायालय में दायर की गई थी। इसके बाद इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया और उन्हें इस न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं/अपीलों के एक समूह के साथ जोड़ कर और अशोका स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य को निपटान के लिए मुख्य मामला बना दिया।

8. तदनुसार, अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड को अन्य संबंधित मामलों के साथ मुख्य प्रश्न तय करने के लिए विचार के लिए लिया गया था कि क्या भारत संघ द्वारा बनाई गई ई-नीलामी योजना विधिसम्मत थी या नहीं। दूसरे शब्दों में, सवाल यह था कि उच्च न्यायालय का कौन सा दृष्टिकोण सही था– एक जिसने योजना को विधिसम्मत माना या दूसरा जिसने योजना को कानून की दृष्टि से खराब माना?

9. इस न्यायालय ने 12.12.2005 को अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2006) 9 एससीसी 228 में कई

अंतरिम आदेशों को संशोधित करते हुए एक सामान्य अंतरिम आदेश पारित करके, रिट याचिकाकर्ताओं को कोयले की अधिसूचित कीमत के अलावा हर बार कोयले की आपूर्ति का दावा करने पर बढ़ी हुई कीमत का 33-1/3% भुगतान करने और योजना में निर्धारित कोयले की बढ़ी हुई कीमत के शेष 66-2/3% के लिए जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

10. इस न्यायालय ने 01.12.2006 को अशोक स्मोकलेस कोल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 2 एससीसी 640 में दिए गए अपने अंतिम निर्णय द्वारा, रिट याचिकाओं को अनुमति दी और माना कि ई-नीलामी योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए, संविधान के दायरे से बाहर है। तदनुसार, संपूर्ण ई-नीलामी योजना रद्द कर दी गई। इस निर्णय के आलोक में, उच्च न्यायालयों के फैसले, जिन्होंने योजना को बरकरार रखा था, को रद्द कर दिया गया, जबकि जिन उच्च न्यायालयों ने योजना को अधिकारातीत घोषित किया था, उन्हें बरकरार रखा गया। परिणामस्वरूप, इस निर्णय के आलोक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कई रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया। इसके बाद स्थानांतरण याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं में दिनांक 30.10.2007 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया, जिसके लिए जमानत/बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी। जहां तक वर्तमान कंपनियों का सवाल है, रिट याचिकाओं में उनका दावा 2005 के अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों के लिए था।

11. अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) में दिए गए निर्णय ने समान रूप से स्थित कोयला उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे कि पटना, कलकत्ता, झारखंड आदि में कई रिट याचिकाएं दायर करने को जन्म दिया, जिसमें कोयला कंपनियों के खिलाफ परमादेश की मांग करते हुए ब्याज सहित अतिरिक्त राशि

जो कोयला कंपनियों द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं से योजना के अनुसार वसूल की गई थी उन्हें वापस करने की मांग की गई थी।

12. पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भगवती कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य (सीडब्ल्यूजेसी 7753/2008) में पारित दिनांक 01.07.2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह योजना के तहत कोयले की अधिसूचित कीमत से अधिक रिट याचिकाकर्ताओं से एकत्र की गई पूरी राशि 12% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।

13. इस आदेश से व्यथित होकर सीसीएल ने 2009 की एल.पी.ए. संख्या 1094 दायर की। दिनांक 17.02.2010 के आदेश से, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी, लेकिन अतिरिक्त प्रतिदाय राशि पर देय ब्याज की दर 12% से घटाकर 6% कर दी। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17406/2010 दायर की। आदेश दिनांक 19.07.2010 द्वारा, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और खंड पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

14. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कोयला व्यापारी (तेतुलिया कोक प्लांट (पी) लिमिटेड) द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसी तरह की रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को योजना के तहत उनके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की ब्याज सहित वापसी की मांग की गई थी। उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 04.10.2010 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वह संपूर्ण राशि वापस करने का निर्देश जारी किया, जो उन्होंने योजना के अनुसार रिट याचिकाकर्ता से अधिक एकत्र

की थी। व्यथित होकर, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम टेटुलिया कोक प्लांट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2011) 14 एससीसी 624 में दिनांक 10.08.2011 के तर्कसंगत आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

15. यह ई-नीलामी योजना की वैधता के संबंध में इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ है, जो अंततः 1.12.2006 को रिट याचिकाकर्ताओं (कोयला उपभोक्ता/व्यापारी/आपूर्तिकर्ता) के पक्ष में समाप्त हो गई जब इस न्यायालय ने अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (सुप्रा) के मामला में ई-नीलामी योजना को रद्द कर दिया और 19.07.2010 को जब इस न्यायालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया और पटना उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की, जिसमें अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (ऊपर) में कोयला कंपनियों द्वारा वसूल की गई अतिरिक्त राशि 6% की दर पर ब्याज के साथ, जो योजना को कानूनन खराब घोषित किया जाने के परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ताओं को देय हो गई थी, की वापसी का निर्देश दिया गया था और अंततः 10.08.2011 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम टेटुलिया कोक प्लांट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (ऊपर) में जब इस न्यायालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जो कि अतिरिक्त राशि की वापसी के समान मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुई थी, जो ई-नीलामी योजना को कानूनन खराब घोषित करने के परिणामस्वरूप देय हो गई थी, वर्तमान कंपनियों ने 10.08.2010 और 07.09.2010 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें से ये अपीलें उठीं और कोयले की अधिसूचित कीमतों और ई-नीलामी

योजना के अनुसार तय की गई कीमत के बीच भुगतान किए गए अंतर की पूरी अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस करने का दावा किया।

16. कंपनियों के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा ई-नीलामी योजना को कानूनन खराब घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप वे सीसीएल से ब्याज सहित अतिरिक्त राशि की वापसी पाने की हकदार थीं और इसके अलावा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए इस न्यायालय के दो निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में क्योंकि उनके मामले सभी प्रकार से इस न्यायालय द्वारा तय किए गए इन दोनों मामलों के रिट याचिकाकर्ताओं के समान थे। वर्तमान कंपनियों जैसे अन्य व्यापारियों ने भी संबंधित कोलफील्ड कंपनियों के खिलाफ समान राहत का दावा करते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं।

17. सीसीएल ने मूलतः दो आधारों पर रिट याचिकाओं का विरोध किया। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी और कमियाँ रहने के आधार पर रिट याचिका खारिज करने योग्य थी क्योंकि यह अप्रैल 2005 से अक्टूबर 2005 में किए गए अतिरिक्त भुगतान की वापसी का दावा करने के लिए वर्ष 2010 में दायर की गई थी। दूसरे स्थान पर, यह तर्क दिया गया कि तथ्यों के विवादित मुद्दों से जुड़े रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चलते अनुचित संवर्धन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता रिट क्षेत्राधिकार में किसी भी अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करने के हकदार नहीं थे।

18. एकल न्यायाधीश ने सीसीएल की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सीसीएल को ई-नीलामी योजना के तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सीसीएल को भुगतान की गई पूरी अतिरिक्त राशि ऐसी राशि पर

6% की दर से देय ब्याज के साथ रिट याचिकाकर्ताओं को वापस करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया।

19. व्यथित महसूस करते हुए, सीसीएल ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एलपीए दायर किया, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न हुईं। आक्षेपित आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सबसे पहले, रिट याचिकाकर्ताओं का दावा किसी मौलिक या वैधानिक अधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुबंध पर आधारित था और इसलिए यह कायम रखने योग्य नहीं था और दूसरी बात, दावा इस न्यायालय या/और उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न में राशि वापस करने के लिए जारी किए गए किसी भी निर्देश पर आधारित नहीं था और अंततः रिट याचिका परिसीमन द्वारा वर्जित थी। जहां तक अनुचित संवर्द्धन के सिद्धांत से संबंधित सीसीएल के तर्क का सवाल है, उसे खंड पीठ का समर्थन नहीं मिला और तदनुसार सीसीएल के खिलाफ निर्णय लिया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे में विवादित तथ्यों का निर्णय करना शामिल नहीं था, इसलिए, यह रिट याचिकाओं में न्यायनिर्णयन के लिए सक्षम था।

20. उपरोक्त मुद्दों पर डिवीजन बेंच के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।

> "हम तथ्य के विवादित प्रश्नों के आधार पर रिट याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में श्री पाराशरण से सहमत होने में असमर्थ हैं। रिट याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट बयान दिया है कि 12 दिसंबर 2005 से पहले उन्होंने अपीलकर्ताओं से ई-नीलामी द्वारा निर्धारित दर पर यानी अधिसूचित दर से अधिक दर पर कोयला खरीदा था। रिट याचिकाकर्ता बिक्री आदेशों का विवरण, आपूर्ति की तारीख और मात्रा, भुगतान की

गई कीमत और वापस की जाने वाली राशि का विवरण भी रिकॉर्ड पर लाए है। रिट याचिकाओं में दिए गए उक्त विशिष्ट बयानों का अपीलकर्ताओं द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया है। एक मात्र बयान कि रिट याचिकाओं में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, याचिकाओं को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा। विशिष्ट खंडन के अभाव में, विवाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाता है। हम इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे को अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों पर खारिज करने की आवश्यकता है। मौजूदा मामला अपीलकर्ता और रिट याचिकाकर्ताओं के बीच एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन है। कर/चुंगी/शुल्क के रूप में सरकार को देय वैधानिक बकाया के संबंध में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत विकसित किया गया है। इस सिद्धांत को अभी तक सरकार के वाणिज्यिक लेनदेन तक विस्तारित नहीं है।

....

हमारी राय में, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, रिट याचिकाकर्ता राहत के हकदार नहीं हैं।

(i) रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया प्रतिदाय का दावा मौलिक या वैधानिक अधिकार पर आधारित नहीं है;

(ii) रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया प्रतिदाय बिक्री और खरीद के अनुबंध से उत्पन्न होता है;

(iii) ऐसी रकम की वापसी के लिए दावा उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश द्वारा समर्थित नहीं है; माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और;

(iv) निर्विवाद रूप से, दावा सिविल कार्रवाई के लिए निर्धारित परिसीमन अवधि की समाप्ति के बाद किया गया है।"

21. व्यथित महसूस करते हुए, दोनों पक्षों यानी रिट याचिकाकर्ताओं (कंपनियों) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें दायर की हैं।

22. जहां तक रिट याचिकाकर्ताओं (कंपनियों) का सवाल है, उन्होंने निष्कर्षों के खिलाफ अपील दायर की है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं, जबकि जहां तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) का सवाल है, उन्होंने अनुचित संवर्धन के निष्कर्षों को चुनौती दी है, जिसका फैसला खंड पीठ ने उनके खिलाफ दिया था।

23. इस तरह पूरा विवाद अब मूल रिट याचिकाओं के दोनों पक्षों के अनुरोध पर इन अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।

24. उभयपक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया।

25. कंपनियों (रिट याचिकाकर्ताओं) की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.डी. संजय ने खंड पीठ के आक्षेपित फैसले की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए पांच प्रस्तुतियाँ देने का आग्रह किया। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच ने सीसीएल द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देने में गलती की, जिससे रिट याचिकाओं को खारिज करने में गलती हुई, जिन्हें एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) ने सही

तरीके से अनुमति दी थी। उनके अनुसार एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए सीसीएल की अपीलें खारिज कर दी जानी चाहिए थी।

26. दूसरा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि खंड पीठ ने यह मानने में गलती की कि कंपनियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थीं क्योंकि जिस दावे के लिए रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, वह किसी वैधानिक या मौलिक अधिकारों पर आधारित नहीं था, बल्कि कंपनियों के संविदात्मक अधिकार पर आधारित था। विद्वान वकील के अनुसार, इस मुद्दे पर निष्कर्ष पूरी तरह से अरक्षणीय है क्योंकि इस मुद्दे पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया गया था और निपटाया गया था और इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, उनका कहना था कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) में दिए गए इस न्यायालय के निष्कर्ष उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी थे, दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

27. तीसरा, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि खंड पीठ ने यह मानने में गलती की कि कंपनियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं परिसीमन द्वारा वर्जित थीं क्योंकि उन्हें कार्रवाई के कारण की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, यह निष्कर्ष इस कारण से कानून में समान रूप से अरक्षणीय है कि पहले इस मुद्दे पर विचार किया गया, निपटाया गया और फिर ईस्टर्न कोलफील्ड्स मामले में इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया; दूसरा, अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करने के लिए रिट याचिका दायर करने की कार्रवाई का कारण 19.07.2010 को उत्पन्न हुआ जब सेंट्रल कोलफील्ड्स (सीसीएल) द्वारा दायर एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया (अनुलग्नक-14) जिससे अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करने के लिए अंततः संबंधित विवाद का निपटारा हो गया; तीसरा,

हालांकि परिसीमन का कानून रिट याचिकाओं पर लागू नहीं होता है, फिर भी कंपनियों ने सीसीएल के मामले में इस न्यायालय द्वारा एसएलपी खारिज करने की तारीख (19.07.2010) से एक महीने (10.08.2010) के भीतर रिट याचिकाएं दायर कीं और इसलिए रिट याचिकाओं को कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से उचित समय के भीतर दायर किया माना जाना चाहिए था, दूसरे शब्दों में, इसे देरी और कमियों के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

28. चौथा, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक बार समान स्थिति वाले व्यक्ति के अनुरोध पर प्रश्नगत मुद्दों को इस न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया था, तो प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत पर राज्य या/और उसके साधन के खिलाफ इस तरह के निर्णय का लाभ पाने का हकदार था। चूंकि कंपनियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के मामले रिट याचिकाकर्ताओं के मामले के समान थे, जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में पक्षकार थे, जिसमें सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी और इस न्यायालय में अंततः खारिज कर दिया गया था, सीसीएल इस न्यायालय को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) मामले में लिए गए फैसले के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए मनाने के लिए इन अपीलों में फिर से वही दलीलें उठाने का हकदार नहीं था, सिवाय इसके कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में यहां अपीलकर्ताओं जैसे सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान लाभ देने के लिए दिए गए इस न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया जाए।

29. पाँचवाँ, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि खंड पीठ ने सीसीएल के खिलाफ अनुचित संवर्धन के मुद्दे का सही फैसला किया क्योंकि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) में यह न्यायालय पहले ही उक्त याचिका जिसमें कोई योग्यता नहीं है को खारिज कर चुका है। दूसरे शब्दों में, दलील यह थी कि अनुचित संवर्धन के मुद्दे पर खंड पीठ

का निष्कर्ष ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप था और इसलिए सीसीएल द्वारा दायर अपीलों को खारिज करके इस न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। विकल्प में, यह भी आग्रह किया गया कि सीसीएल द्वारा दायर अपीलें सुनवाई योग्य नहीं थीं क्योंकि जब पूरा फैसला उनके पक्ष में था जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपील की अनुमति दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में केवल निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

30. कुछ कंपनियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने अपनी अपीलों में कुछ तथ्यात्मक विशिष्ट विशेषताओं की ओर इशारा करते हुए अन्य कंपनियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.डी. संजय के उपरोक्त तर्कों को अपनाया।

31. इसके विपरीत, सीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने खंड पीठ द्वारा दिए गए तर्क और अंतिम निष्कर्ष पर दिए गए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि दोनों को बरकरार रखा जाना चाहिए। विद्वान वकील ने अपनी अपील के समर्थन में आगे आग्रह किया कि खंड पीठ ने सीसीएल के खिलाफ अनुचित संवर्धन के मुद्दे पर निर्णय लेने में गलती की। विद्वान वकील के अनुसार, फैसला उनके पक्ष में रिट याचिकाओं को खारिज करने का होना चाहिए था।

32. उभय पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद, हम कंपनियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के विद्वान वकील की दलीलों में बल पाते हैं और इसलिए हम रिट याचिकाकर्ताओं (कंपनियों) द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देने के इच्छुक हैं।

33. हमारे सुविचारित विचार में, इन मामलों में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों, जिनमें ऊपर उल्लिखित पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतीकरण

शामिल हैं, इस न्यायालय द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पहले ही तय किए गए थे और इसलिए रिट याचिकाएं और उससे उत्पन्न होने वाली अपीलों का निर्णय उक्त निर्णय में निर्धारित कानून के आलोक में रिट अदालत और अपीलीय अदालत (खंड पीठ) द्वारा किया जाना चाहिए था।

34. यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय 10.08.2011 को रिट याचिका की लंबितता के दौरान प्रदान किया गया था, फिर भी न तो एकल न्यायाधीश जिसने 02.04.2012 को रिट याचिका का फैसला किया था और न ही 14.12.2012 को अपील का फैसला करने वाली खंड पीठ ने फैसले पर ध्यान दिया और अपने संबंधित निर्णयों में इसका उल्लेख करना तो दूर की बात है। इसलिए, हम इस मुद्दे को तय करने में नीचे की दो अदालतों के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकते, हालांकि यह उलटफेर का था।

35. संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसलिए, जब एक बार इस न्यायालय ने 10.08.2011 को एक तर्कसंगत आदेश पारित करके ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में मुद्दे का फैसला किया, तो उक्त निर्णय में घोषित अनुपात निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर समान प्रकृति के लिस का निर्णय करते समय इसे क्रियान्वित करने के लिए बाध्यकारी था। इसलिए, नीचे की दोनों अदालतें उक्त निर्णय पर ध्यान देने के लिए कानूनी बाध्यता के अधीन थीं और फिर उसमें निर्धारित कानून के अनुरूप रिट याचिका/अपील पर निर्णय लेना चाहिए था। ऐसा इसलिए अधिक था क्योंकि दोनों मामलों में शामिल विवाद की प्रकृति समान थी।

36. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोनों न्यायालय ऐसा करने में विफल रहे जिससे आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि में खराब हो गया।

37. जब हम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निर्णय का अध्ययन करते हैं, तो हमें मौजूदा मामले के तथ्यों और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में शामिल मामले के तथ्यों के बीच कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं मिलता है। पैराग्राफ 9, 10 और 11 को उद्धृत करना उचित है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ऊपर) में निर्णय जो इन दोनों मामलों में समानता दिखाएगा:

> "9. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कोयले का व्यापार करने वाले व्यापारियों और कंपनियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके ई-नीलामी की योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी। उन याचिकाओं में से कुछ को इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, प्रमुख मामला अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड (2007) 2 एससीसी 640 था जिसे संबंधित मामलों के साथ विचार के लिए लिया गया था और ये थे इस न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया और उक्त निर्णय अब अशोका स्मोकलेस में रिपोर्ट किया गया है। उपरोक्त निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने ई-नीलामी की योजना की वैधता को लेकर रिट याचिकाकर्ताओं की चुनौती को बरकरार रखा है। रिट याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और इस न्यायालय ने माना कि ई-नीलामी की योजना अमान्य थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए, इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया और इस न्यायालय ने ई-नीलामी योजना को रद्द कर दिया।
>
> 10. यहां यह इंगित किया जाना चाहिए कि वर्तमान प्रतिवादी ने उपरोक्त निर्णय दिए जाने से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी

प्रश्नगत रिट याचिका दायर की थी और उसके मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड के निपटान के बाद, प्रतिवादी द्वारा यहाँ दायर रिट याचिका, जो लंबित थी, पर भी विचार किया गया और अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद उसे अनुमति दी गई क्योंकि उस निर्णय के अनुसार, इस न्यायालय ने पूरी योजना को अमान्य और संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया है। इसलिए, उक्त योजना के अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई अवैध और अमान्य है। उक्त निर्णय के अनुपात का पालन करते हुए इस न्यायालय ने कोयला कंपनियों को ई-नीलामी योजना के तहत अधिसूचित मूल्य से अधिक भुगतान किये गये कोयले की कीमत वापस करने का निर्देश दिया। इस तरह के भुगतान कैसे किए जाने हैं, इसके लिए कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निष्कर्षों की पुष्टि करके और उसके समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का विश्लेषण करके बरकरार रखा था।

11. हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वर्तमान याचिका में जिसे भी चुनौती दी गई है वह केवल एक अंतरिम आदेश है। ऐसा नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं ने रिट याचिका में ई-नीलामी योजना की वैधता को भी चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने केवल एक अंतरिम प्रार्थना का निपटारा नहीं किया है, बल्कि अपने निर्णय और आदेश दिनांक 25-3-2010 द्वारा संपूर्ण

रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। नतीजतन, यह भी माना जाना चाहिए कि जब इस न्यायालय द्वारा पूरी योजना को रद्द कर दिया गया है, तो कोयला कंपनी द्वारा उक्त ई-नीलामी के बाद जो भी कार्रवाई की गई है, उसे भी अवैध घोषित कर दिया गया है और, इसलिए, कोयला कंपनी उस पूरे पैसे को वापस करने के लिए उत्तरदायी हो गई है जो अधिसूचित मूल्य से अधिक एकत्र किया गया था। यह योजना को रद्द करने का परिणाम है और यही बात इस न्यायालय द्वारा भी दोहराई गई थी जब अवमानना याचिकाएं दायर की गईं और उनका निपटारा किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड के निर्णय का प्रभाव केवल उन मामलों तक ही सीमित होगा जो इस न्यायालय के समक्ष थे, और उन सभी मामलों के लिए नहीं जो उस स्तर पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित थे, कम से कम उन मुद्दों के लिए जो प्रकृति में सामान्य हैं।"

उपरोक्त पैराग्राफों के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स मामले (सुप्रा) में बिना किसी अनिश्चित शर्तों के कहा है कि अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का लाभ उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो उन मामलों में पक्षकार थे, बल्कि यह इस तथ्य की परवाह किए बिना सभी के लिए होगा कि वे मामले में पक्षकार थे या नहीं। (ऊपर निकाले गए भाग का पैरा 11 देखें)। इसलिए, इस न्यायालय ने अतिरिक्त राशि की वापसी की राहत को बरकरार रखा, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ता को दी गई थी और तदनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

38. इसी तरह, इस न्यायालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा उठाए गए अनुचित संवर्धन के सवाल से स्पष्ट रूप से निपटते हुए पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित शब्दों में कोई योग्यता नहीं पाते हुए उक्त प्रस्तुतीकरण को खारिज कर दिया:

> "12. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाता लाभ के हकदार नहीं हैं, यदि वे अन्यथा अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों पर हकदार हैं। हमने बहस के दौरान विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कहा कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई रिट याचिका में ऐसी कोई दलील दी गई थी। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यह दिखाने में असमर्थ रहे कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर दलीलों में अन्यायपूर्ण संवर्धन के बारे में ऐसा कोई बचाव या दलील दी गई थी। इस तरह के मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी बहस नहीं की गई क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहा गया है कि ऐसा मुद्दा खंड पीठ के समक्ष उठाया गया था। लेकिन हम दलीलों में इसे उठाया हुआ नहीं पा सके और न ही इस पर विचार किया गया। लेकिन फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस तरह की याचिका पर बहस की गई थी। हालाँकि, रिकॉर्ड देखने पर हमें पता चलता है कि वर्तमान अपील में दायर अपील के ज्ञापन में भी ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है। हालाँकि, रिकॉर्ड देखने पर हमें पता चलता है कि वर्तमान अपील में दायर अपील के ज्ञापन में भी ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है। इसलिए, रिट याचिका में या इस

न्यायालय के समक्ष अन्यायपूर्ण संवर्धन की दलील दिए बिना, हम उसे तर्क के समय दलील पर बहस करने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं और विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं को पहली बार बहस के चरण में की गई ऐसी दलील के बारे में कोई सूचना नहीं थी।"

39. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुचित संवर्धन के मुद्दे पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कहने पर इस न्यायालय के समक्ष रखी गई स्पष्ट चुनौती को खारिज कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि किस आधार पर, ईस्टर्न कोल कंपनी जैसी एक अन्य कोयला कंपनी को इन कार्यवाहियों में फिर से वही दलील उठाने की अनुमति दी जा सकती है, केवल इसलिए कि यह मामला किसी अन्य उच्च न्यायालय से उत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्दों में, हमारी सुविचारित राय है कि इस न्यायालय ने इसी तरह के विवाद से निपटने के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स (सुप्रा) के मामले में अनुचित संवर्धन के मुद्दे को खारिज कर दिया है, यही मुद्दा अब किसी अन्य कोयला कंपनी के पास इसी तरह की लंबित कार्यवाही में उठाने के लिए उपलब्ध नहीं है। यह तब और भी अधिक है जब दोनों मामलों में कोई विशिष्ट विशेषता हमारे ध्यान में नहीं लाई गई।

40. अब रिट याचिकाकर्ताओं को देय अतिरिक्त राशि की वापसी के मुद्दे पर आते हुए, हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने पैरा 13 में उक्त मुद्दे की जांच की है और निम्नलिखित शब्दों में रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया है:

"13. वर्तमान मामले में, यह अपीलकर्ता द्वारा अधिक वसूली गई कीमत की वापसी का मामला है, न कि किसी प्रकार के कर या शुल्क के भुगतान का। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने ऐसी कोई दलील उठाए

बिना कई अन्य पक्षों को पहले ही वसूल की गई अतिरिक्त राशि वापस कर दी है। यदि किसी पक्ष द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी किया जाता है, तो परिणाम भुगतना पड़ता है और वे उन पक्षों को धन वापस करने के लिए बाध्य होते हैं जिनसे अतिरिक्त राशि वसूल की गई है। ऐसी किसी दलील के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज़ भी नहीं रखा गया है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब इस न्यायालय में ऐसी कोई दलील नहीं उठाई गई हो।"

41. उपरोक्त निर्धारित कानून के आलोक में, हमें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले के रिट याचिकाकर्ताओं के साथ समानता के आधार पर वर्तमान कंपनियों (रिट याचिकाकर्ताओं) को ऐसे कानून का लाभ देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।

42. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करने के लिए रिट याचिका दायर करने का अधिकार इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले 19.07.2010 को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद उत्पन्न हुआ जब इस न्यायालय ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा दायर एसएलपी को सिरे से खारिज कर दिया और इसी मुद्दे पर पटना उच्च न्यायालय के तर्कसंगत आदेश को बरकरार रखा। यह विवाद में नहीं है कि कंपनियों ने 10.08.2010 को (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर) रिट याचिकाएं दायर कीं। वास्तव में, कंपनियां ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (10.08.2011) के मामले में दिए गए निर्णय के बाद भी रिट याचिकाएं दायर कर सकती थीं क्योंकि इस मामले में, इस न्यायालय ने अंततः कोयला कंपनियों की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए गुण-दोष के आधार

पर एक तर्कसंगत निर्णय दिया और रिट याचिकाकर्ताओं के उस अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा, जो उन्होंने योजना के अनुसार सीसीएल और अन्य कोयला क्षेत्रों को भुगतान किया था।

43. इसलिए, हम खंड पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं जब उसने देरी और कमियों के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर रिट याचिकाओं पर सही ढंग से विचार किया और रिट याचिका में कंपनियों द्वारा किए गए दावे के अनुसार राहत प्रदान की और हमारी राय में, खंड पीठ को एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखना चाहिए था।

44. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में कंपनियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के विद्वान वकील द्वारा आग्रह की गई सभी पांच दलीलों को इस अदालत में स्वीकार कर लिया गया है, और इसलिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निर्धारित कानून पर भरोसा करते हुए इन अपीलों पर निर्णय लेते समय वे स्वीकार किए जाने योग्य हैं। इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णय विधियों पर ध्यान देकर इन प्रस्तुतियों को उनके संबंधित गुणों के आधार पर फिर से निपटाने के लिए आवश्यक नहीं समझते हैं।

45. चूंकि हमने अनुचित संवर्धन के संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड्स इंडिया लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा उठाए गए आधार को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया है, और इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि केवल निष्कर्ष के खिलाफ उनके द्वारा दायर की गई अपील सुनवाई योग्य है या नहीं। हमने यह भी पाया कि सीसीएल द्वारा दायर अपीलों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 22 के तहत क्रॉस आपत्ति के ज्ञापन के रूप में मानने या परिवर्तित करने के लिए सीसीएल

के विद्वान वकील द्वारा कंपनियों द्वारा दायर अपीलों में कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, ताकि वे आदेश 41 नियम 22 के तहत विवादित निष्कर्ष को चुनौती देने में सक्षम हो सकें। हम इस प्रश्न की भी जांच नहीं करना चाहते हैं कि क्या अनुच्छेद 136 के तहत दायर एसएलपी से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी की ओर से प्रति आपत्ति की अनुमति है या नहीं और इन सभी प्रश्नों को भविष्य में अवसर आने पर उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

46. मामले से अलग होने से पहले, हम यह कहना उचित समझते हैं कि यह मामला हमें फर्म कालूराम सीताराम बनाम द डोमिनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1954 बॉम्बे 50 में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.सी. छागला द्वारा की गई सूक्ष्म टिप्पणियों की याद दिलाता है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपनी लेखन की विशिष्ट शैली में इस प्रकार कहा:

> "....हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिला है कि जब राज्य किसी नागरिक केसाथ व्यवहार करता है तो उसे आम तौर पर तकनीकी पहलुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला उचित है, भले ही कानूनी बचाव उसके लिए खुले हो, उसे कार्य करना चाहिए, जैसा कि प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने कहा है, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में..."

47. सीसीएल द्वारा अपनाए गए रुख और जिस तरह से उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में सभी चरणों में इस न्यायालय द्वारा उनके फैसले के बावजूद समान दलीलें देकर मामले लड़े, उसे ध्यान में रखते हुए हमें इससे यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि पिछले मुकदमों में इस न्यायालय द्वारा नागरिकों के

पक्ष में निर्धारित किए गए वैध दावे जिनकी जानकारी सीसीएल को थी, को विफल करने के लिए सीसीएल द्वारा अरक्षणीय दलीलें उठाई जा रही थीं।

48. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें यानी 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 12925-12926, 13286, 14148, 14576, 15992 और 15993 से उत्पन्न अपीलें अनुमति के योग्य हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है हालांकि अलग-अलग कारणों पर जो हमने ऊपर दिए हैं। परिणामस्वरूप, विवादित निर्णयों/आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।

49. परिणामस्वरूप, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दायर अपीलें– 2013 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 14430, 15985, 15986, 15987, 15989, 15990 और 15991 से उत्पन्न सिविल अपीलें खारिज कर दी गईं।

50. सीसीएल को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का सत्यापन करे और फिर रिट याचिकाकर्ताओं को उनके दावे के विरुद्ध भुगतान की गई किसी भी राशि का समायोजन करने के बाद, शेष राशि 6% की दर से ब्याज सहित संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं (कंपनियों) को वापस कर दे। इसे तीन महीने के अंदर पूरा किया जाए.

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफ़िशयल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****